भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3600

(जिसका उत्तर सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021/29 अग्रहयण, 1943 (शक), को दिया जाना है)

विमुद्रीकरण के प्रभाव

3600. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने व्यापार, रोजगार, कृषि और गरीबी पर विमुद्रीकरण के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा व्यवसाय, रोजगार और गरीबी उपशमन पहलों के प्रभाव से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) सरकार ने पुराने मुद्रा नोटों के बदले कुल कितनी राशि का विनिमय किया है; और

(घ) क्या विमुद्रीकरण के बाद कोई अध्ययन किया गया है या कोई रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): किसी देश का आर्थिक विकास संरचनात्मक, विदेशी, वित्तीय और मौद्रिक कारकों सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।इसलिए, अन्य कारकों से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण के प्रभाव को इंगित करना मुश्किल है।आरबीआई ने मार्च 2017 में "विमुद्रीकरण का व्यापक आर्थिक प्रभाव - एक प्रारंभिक आकलन" शीर्षक से एक अध्ययन प्रकाशित किया है, जो आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।अध्ययन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खातों की संख्या में तेज वृद्धि हुई है और ऐसे खातों की जमा राशि में भी वृद्धि हुई है। विमुद्रीकरण के पश्चात वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2017-18 में डिजिटल भुगतान की कुल मात्रा 1459.02 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 4371.18 करोड़ हो गई है।बैंक खातों और डिजिटल लेनदेन तक पहुंच में वृद्धि के इन दो रुझानों में कम भ्रष्टाचार, वित्तीय सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि और अर्थव्यवस्था के अधिक औपचारिककरण से जुड़े लाभ हैं। जहां तक कुल राशि के आदान-प्रदान का संबंध है, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2021 तक एसबीएन के लिए 15,31,094 करोड़ रु (राउंड ऑफ) का भुगतान किया जा चुका है।

******